हरियाणा की चीनी मिलों की आड़ में लूट का बड़ा स्कैंडल

वाई.के. रज्जन

हरियाणा में चीनी मिलों को जिस तरह पालापोसा जा रहा है, वह एक स्कैंडल से कम नहीं है। यह गोरखधंधा है, जिसमें शामिल है हरियाणा की बीजेपी सरकार, मिल मालिक, बैंक, चीनी को कंट्रोल करने वाली लॉबी। यह गोरखधंधा हरियाणा की सहकारी यानी सरकारी कोआपरेटिव चीनी मिलों से लेकर प्राइवेट चीनी मिलों तक में चल रहा है।

पहले किसानों की बात

इन सभी पर किसानों का करोड़ों रुपये बकाया है। लेकिन सरकार इनको कर्ज दे देकर सफेद हाथी की तरह पाल रही है। तय नियम मुताबिक जिस दिन किसान अपना गन्ना शुगर मिल मे डालता है उस दिन से चौदह दिन के अंदर किसान को उस गन्ने का भुगतान होना चाहिए, लेकिन प्रदेश की किसी भी सहकारी व प्राइवेट शुगर मिल में इस नियम का पालन नहीं किया जाता।

प्रदेश की तीन प्राइवेट चीनी मिलों यमुनानगर सरस्वती शुगर मिल, करनाल की पिकाडली शुगर मिल व नारायणगढ शुगर मिल समेत 14 चीनी मिलों पर किसानों का 135 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। भुगतान न करने वालों में दो तिहाई चीनी मिलें 14 में से 11 सहकारी हैं, जिनके जिम्मे किसानों का 75 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है। किसानों का प्राइवेट चीनी मिलों पर 60 करोड़ बकाया है तो सरकार की देनदारी है 75 करोड़ की।

सरस्वती शुगर मिल ने इस सीजन में 429 करोड 88 लाख रुपये का गन्ना खरीदा था। यमुनानगर के अलावा अम्बाला, कुरुक्षेत्र व करनाल जिलों के करीब पचास हजार किसान इस शुगर मिल से जुड़े हैं। शुगर मिल ने करीब सवा दो सौ करोड़ का भुगतान तो शुगर मिल की पैराई के दौरान कर दिया था, लेकिन उसके बाद चीनी के दाम गिरने से शुगर मिल के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। सरकार को मिल प्रबंधकों ने स्थिति बताई तो सरकार ने करीब 200 करोड़ का ऋण देने का निर्णय लिया।

सहकारी मिलों की तरफकिसानों का 75 करोड़ का भुगतान बाकी है। अकेले रोहतक की रोहतक व महम शुगर मिल की तरफ44 करोड़ का भुगतान बाकी है। सोनीपत के गोहाना में स्थित सहकारी मिल की तरफ छह करोड़ का भुगतान बाकी है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मिल पर करीब 27 करोड़ का भुगतान बाकी है। पलवल सहकारी पर भी किसानों की देनदारी है।

कैसे चल रहा है गोरखधंधा

हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ के ही मुताबिक नारायणगढ़ चीनी मिल पर किसानों का अभी भी 5,122.79 लाख बकाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले महीने कैबिनेट मीटिंग बुलाकर इस चीनी मिल के लिए 45 करोड़ का लोन सरकार की गारंटी पर दिलाने का फैसला लिया। हरियाणा सरकार अपने सहकारी बैंक हारको से यह लोन नारायणगढ़ चीनी मिल को दिलाना चाहती है। पंजाब.हरियाणा हाई कोर्ट ने इस लोन को देने पर बैंक को रोक दिया है। सहकारी बैंक के कर्मचारियों की यूनियन ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा कि चीनी मिल ने घाटा बताकर 45 करोड़ के लोन के लिए बैंक की मदद मांगी, जिसे बैंक ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन अगर यह लोन उस चीनी मिल को दिया गया तो बैंक की अपनी स्थिति बदतर हो जाएगी क्योंकि वह एक बीमार चीनी मिल है जो इस लोन को चुका नहीं पाएगी। वैसे भी रिजर्व बैंक आफ इंडिया का निर्देश है कि बैंक किसी बीमार कंपनी को लोन न दें। यह चीनी पहले ही वित्तीय संस्थाओं से 100 करोड़ का लोन लेकर खुद को गिरवी रख चुकी है। कंपनी के डायरेक्टर्स की चल.अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर वैसे भी रोक लगी हुई है। अगर शेयर मार्केट इंडेक्स देखें तो इस चीनी मिल को हर तिमाही में घाटा हो रहा है। यह आंकड़ा चीनी मिल छिपा नहीं सकती लेकिन हरियाणा सरकार के पास घाटे में डूबती जा रही इस चीनी मिल के आंकड़ों को देखने की फुरसत नहीं है। वजह साफहै कि पैसे की इस बंदरबांट में सारे शामिल हैं। यह मिलजुल कर खाने का मामला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा में राज किसी भी पार्टी का हो, इस चीनी मिल की चिंता हर पार्टी की सरकार करती रही है। चौटाला के शासनकाल में इस चीनी मिल को 7 करोड़ का लोन मंजूर किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद अब मौजूदा सरकार ने भी इस प्राइवेट चीनी मिल पर मेहरबानी दिखाई है।

इन्हें भी जानिए

दो और प्राइवेट मिलों सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर को हरियाणा सरकार ने 34.51 करोड़ और पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज ;चीनी मिल को 10.38 करोड़ का लोन मंजूर किया है। आंकड़ों से साफहै कि नारायणगढ़ चीनी मिल को हर बार ज्यादा लोन सरकार मंजूर करती रही है जो अपने आप में एक बड़ा स्कैंडल है। हरियाणा के कुछ आईएएस अफसर अंतरंग बातों के दौरान कहते हैं कि राज्य की चीनी मिलें हमारे लिए दुधारू गाय हैं।

रोहतक चीनी मिल का गोरखधंधा

सरकार भाली आनंदपुर गांव में नई चीनी मिल लगा रही है। लेकिन लोकायुक्त की जांच में पाया गया कि पुणे की जिस कंपनी एस.एस. इंजीनियर्स को यह मिल लगाने का ठेका 98.5 करोड़ रुपये में दिया गया था, उसमें रिफाइंड शुगर प्लांट की जगह सस्ता वाला सल्फर शुगर प्लांट लगा दिया गया। इसके अलावा पुरानी चीनी मिल के तमाम कलपुर्जों को नई चीनी मिल में इस्तेमाल कर लिया गया। चीनी मिल में पैसे की यह बंदरबांट हालांकि पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में हुई थी लेकिन तमाम कारणों से मौजूदा सरकार इस स्कैंडल की जांच को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।

लोन की बंदरबांट

केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को 6000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन मंजूर किया है, जिससे किसानों का देशभर में बकाया 21000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा सके। लेकिन यह सब मायाजाल है। ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन है। हर राज्य में वहां की सरकारें बैंकों से लोन दिलाती है। चीनी मिल मालिक लोन अपनी जेब में डालते हैं। किसानों को गन्ने के रेट का भुगतान होता नहीं है। चीनी मिलें घाटा बताकर भुगतान देने में असमर्थता बता देतें हैं। सरकार उनका कर्ज माफकर देती है। कुछ दिन बाद फिर से उन्हें लोन दिलाया जाता है। यह गोरखधंधा साल दर साल चलता आ रहा है। किसान मजबूर है, वह गन्ना न बेचे तो क्या करे। वह बैंक से कर्ज लेता है तो बैंक रिकवरी के लिए उस पर चढ़ाई कर देते हैं लेकिन नारायणगढ़ चीनी मिल, सरस्वती शुगर मिल, पिकाडली से लेकर अंबानी, अडाणी के बैंक कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। ....जनता जानकर भी अनजान बनी हुई है। इस भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए उसे ही कुछ करना होगा।

टीपू सुल्तान साम्प्रदायवादियों के निशाने पर

हिन्दू और मुसलमान दोनों तरह के साम्प्रदायिक लोग दूसरे धर्मों के मानने वालों के खिलाफ़ भाषा बोलते हैं और इस काम को अंजाम देने के लिये वे इतिहास का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय इतिहास को लेकर हिन्दू साम्प्रदायिक व्यवस्था के दो खास बिंदू हैं, एक-प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता शिखर पर थी लेकिन मध्यकाल में वह मुसलमानों के कारण शिखर से खिसकी और उसका पतन हो गया। मुसलमानों ने निरंकुश होकर शासन किया और हिंदुओं को बेतरह पीड़ित किया। दूसरे, मुसलमानों का शासन विदेशी था केवल उनके धर्म के आधार पर। इसलिये भारतीय समाज के लिये मुसलमान स्थाई तौर पर विदेशी हैं। परंतु इतिहास की समझ रखने वाला व्यक्ति यह जानता है कि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। आजकल हिन्दु साम्प्रदायिक ताकतें सत्ता में हैं और वे सत्ता का इस्तेमाल असहिष्णुता व साम्प्रदायिक विचारधारा को फ़ैलाने के लिये कर रहे हैं जिसमें साम्प्रदायिक तनाव व टकराव की स्थिति उतपन्न हो जाती है। कर्नाटक सरकार द्वारा 18 वीं शताबदी के शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का संघ परिवार व अन्य साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा कड़ा प्रतिरोध किया जा रहा है। इसलिये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में टीपू सुल्तान के बारे में विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच दूसरे युद्ध के दौरान 1782 में हैदरअली को मारे जाने पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा। वह जटिल चरित्रवाला और नये-नये विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। उसने एक नया कैनेंडर लागू किया, सिक्के ढालने की नई प्रणाली लागू की तथा माप-तौल के नए पैमाने अपनाए। उसने अपने पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित आदि विषयों पर पुस्तकें रखी। उसकी फ्रांसिसी क्रान्ति में गहरी दिलचस्पी थी। उसने श्री रंग पट्टन में 'स्वतंत्रता वृक्ष' लगाया और वह फ्रांस के एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया।

टीपू की संगठनिक क्षमता का प्रमाण उसकी सेना है जो उसके अंत तक अनुशासित रही। उसकी पैदल सेना यूरोपीय ढंग की थी जो बंदूकों और संगीनों से सुसज्जित थी, जिनका निर्माण मैसूर में ही होता था। उसने सेना में फ्रांसिसी सैन्य अधिकारियों की भर्ती की, जिन्होंने टीपू की सैन्य टुकड़ियों को प्रशिक्षित किया। अंग्रेजों की नौ-सैनिक शक्ति का मुकाबला करने के लिये एक आधुनिक जल सेना बनाने की कोशिश की, जिसके लिये उसने दो गोदीबाड़े स्थापित किए। जहाजों के मॉडल भी उसने खुद बनाए।

टीपू सुल्तान ने जागीर देने की प्रथा समाप्त करके राजकीय आय बढाने और जमींदारों की पैतृक जागीर को कम करने की कोशिश की। उसके समय में भूराजस्व पैदावार का एक तिहाई था जितना उस समय के अन्य शासकों के शासन में था। परंतु उसने अन्य करों की वसूली पर रोक लगा दी थी। वह भूराजस्व कर में छूट देने में उदार था। उसके समय में मैसूर ने आर्थिक रूप से तरक्की की। जब 1799 में टीपू को हराकर और मारकर अंग्रेजों ने मैसूर पर अधिकार किया तब उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैसूर के किसान मद्रास के उनके अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक समृद्ध था। गबर्नर जनरल सर जौन ने बाद में लिखा कि ''उसके अधिकार क्षेत्र के किसान पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनके श्रम को पोत्साहित किया जाता है तथा पारिश्रमिक दिया जाता है।''

भारतीय शासकों में टीपू सुल्तान अकेला शासक था जिसने सैनिक शक्ति के आधार के रूप में आर्थिक महत्व को समझा। उसने व्यापार और उद्योग को बढावा दिया। उसने व्यापारिक केन्द्र स्थापित किए और व्यापार को नियंत्रित करने के लिये अधिकारियों की नियुति की। उद्योगों को स्थापित करने के लिये विदेशी विशेषज्ञ बुलाए। व्यापार बढाने के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में अपने राजदूत भेजे। उसने चीन के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए। इससे भी ऊपर उसने यूरोपियन कम्पनियों के अनुसार एक व्यापारिक कम्पनी बनाने की कोशिश की।

एक कुशल राजनेता के रूप में उसने 18 वीं शताब्दी के किसी भी अन्य भारतीय शासक से अधिक अच्छी तरह से उस खतरे को पहचाना जो अंग्रेजों ने दक्षिणी भारत और अन्य भारतीय शासकों के लिये पैदा कर दिया था। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसिसियों व नेपोलियन बोनापार्ट से मित्रता स्थापित करके उनसे सैनिक सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न किए। इसके साथ-साथ उसने अपने दूत अरब, कुस्तुंतनिया, फ्रांस और मारीशश भी भेजे जिससे वह अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सैनिक शक्ति बढा सके। इससे अंग्रेज चिंतित हो गए और वे टीपू सुल्तान को अत्यंत खतरनाक दुश्मन के रूप में देखने लगे। इसलिये अंग्रेजों ने टीपू के विरुद्ध मराठों और हैदराबाद के निज़ाम से त्रिदलीय संघ पुन: स्थापित किया और 1799 में टीपू को पराजित कर दिया। परंतु इस युद्ध के दौरान टीपू को विदेशों से कोई सैन्य सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि वे अपनी विषम परिस्थितियों के कारण बेबश थे।

उस समय के शासकों में से टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिये सबसे बड़ा ख़तरा था इसलिये अंग्रेज इतिहासकारों ने टीपू को एक धर्मांध शासक के रूप में पेश किया। परंतु तथ्य इसका समर्थन नहीं करते। यद्यपि वह अपने व्यक्तिगत विचारों में रूढिवादी था तथापि अन्य धर्मों के प्रति अपने रूख में सहिष्णु और प्रबुद्ध था। वह हैदरअली की धार्मिक सहनशीलता की नीति पर चला। हैदरअली द्वारा नियुक्त हिन्दू दिवान व अन्य अनेक अधिकारी उसके शासन में भी कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त उसने अनेक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की। श्रींगेरी मंदिर को मराठा घुड़सवारों ने 1781 में लूट लिया था। टीपू ने इस मंदिर की देवी शारदा की मूर्ति बनाने के लिये धन दिया। उसने श्रींगेरी, नंजन गुड्डु, रंग स्वामी और अन्य कई मंदिरो को नियमित रूप से अर्थिक उपहार दिए। श्रीरंग नाथ का प्रसिद्ध मंदिर उसके महल से केवल 100 राज की दूरी पर सुरक्षित था।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि टीपू सुल्तान अपने समकालीन शासकों में एक कुशल प्रशासक और राजनेता था जिसने अंग्रेजों को देश के लिये सबसे बड़ा खतरा समझा और भारत से बाहर निकालने के लिये एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह अंत तक संघर्ष किया। उस पर धर्मांध होने के आरोप बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं। वास्तव में टीपू एक धर्म निरपेक्ष शासक था। परंतु वह एक मुसलमान शासक था इसलिये संघ परिवार तथा अन्य साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा उसको लेकर असहिष्णुता व साम्प्रदायिक तनाव व टकराव की स्थिति उत्पन्न करके साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है।

-प्रो. जुगल किशोर गुप्ता

तुर्की-ब-तुर्की / बोय पेड़ बबूल के आम कहाँ से होय

''बिहार में जीत पर जो श्रेय लेने वाले थे उन्हें ही अब हार का जवाबदेह होना चाहिये।''

(बिहार चुनाव में भाजपा की करारी हार के संदर्भ में मोदी-शाह-जेटली गिरोह पर निशाना साधते हुए आडवाणी, जोशी, सिन्हा व शान्ता कुमार का संयुक्त बयान)

हमारा कहना है-

 आडवाणी जी आज आपने अपने पट्ट शिष्य नरेन्द्र मोदी को लेकर सही बयानबाज़ी तब की है जब उसने आपको पूरी तरह पट्ट कर रखा है। वरना गुजरात 2002 पोग्राम के बाद, जब आपकी महत्वाकांक्षा में प्रधानमंत्री की कुर्सी इतनी दूर नहीं थी और मोदी इस काम में आपका प्रिय सहयोगी था, आपको अपना आज वाला समीकरण याद नहीं रहा था। उस समय भी यदि जवाबदेही नरेन्द्र मोदी की लगाई होती तो आज आपको ये दिन न देखने पड़ते।

 आडवाणी जी क्या आप भूल गये कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तो बतौर प्रधानमंत्री, मोदी को राजधर्म सिखाने का मन बना लिया था। यह तो संघ के इशारे पर उस समय आप मोदी के पक्ष में अड़ गये और बात आई-गयी हो गयी। यहां तक कि इसका खामियाज़ा आपकी पार्टी को 2004 का लोकसभा चुनाव हार कर चुकाना पड़ा था। तब यदि आपकी पार्टी जीती होती तो वाजपेयी के बीमार पड़ने पर आप ही प्रधानमंत्री होते। आज मोदी को उसकी जवाबदेही आप तब याद दिला रहे हैं जब उसने आपको हीरो से जीरो कर दिया है।

 जवाबदेही का सिद्धान्त तो स्वंय आप पर भी लागू होना चाहिये। इसी नरेन्द्र मोदी के सक्रिय सहयोग से आपने 1989-90 में 'सफ़ल' अयोध्या यात्रा से रामजन्म भूमि आन्दोलन की राजनीतिक लहर पैदा की थी। इसका अन्त दिसम्बर 1992 में बाबरी मस्जिद के आपराधिक विध्वंस के रूप में हुआ। इसको लेकर चल रहे मुकदमे में आप स्वयं को निरपराध बताते आ रहे हैं। सवाल है कि आपको बाबरी ध्वंस और उसके बाद हुई देशव्यापी हिंसा का जवाबदेह क्यों न माना जाये।

 सभी जानते हैं कि नरेन्द्र मोदी जैसे भस्मासुर को पालने-पोसने में आपकी मुख्य भूमिका रही है। इस हिसाब से उसके तमाम कारनामों का जवाबदेह भी आपको ही ठहराया जाना चाहिये। क्या आप में यह साहस है कि अपनी इस भूल को एक सार्वजनिक वक्तव्य के माध्यम से स्वीकार करें?

. हिन्दुस्तान की राजनीति में हमने पहले भी बिल्ली के भागों छींका टूटते देखा है। देवगौड़ा, गुजराल, मोरारजी देसाई इसके उदाहरण हैं। हो सकता है आपके भाग से भी कभी छींका टूट जाय। पर देश की जनता तब भी आपसे यह पूछना नहीं भूलेगी कि श्रेय लेने वाले की जवाबदेही का सिद्धान्त क्या आप बाबरी मस्जिद विध्वंस और मोदी उत्सर्ग मामलों में लागू करेंगे या नहीं?